भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2137
10 दिसंबर, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

डेंगू फैलने के कारण

2137. श्री दीपक अधिकारी (देव):

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपाकरेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में डेंगू के फैलने केकारणों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कोविड वैश्विक महामारी ने डेंगू रोगियों के उपचार को किसप्रकार प्रभावित किया है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) और (ख):

वर्ष 2021 में डेंगू के मामलों की रिपोर्ट मिलने पर बहुविषयक केंद्रीय टीमें 15 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में तैनात की गई थीं। इन टीमों ने देखा कि (i) लंबे समय तक और बीच-बीच में होने वाली बारिशों के परिणामस्वरूप डेंगू वेक्टर के प्रजनन के स्थानों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण डेंगू वेक्टर की संख्या का घनत्व अधिक हो गया। (ii) वेक्टर जनित रोग संबंधी क्षेत्रीय स्टाफ कोविड-19 से जुड़े विभिन्न क्रियाकलापों के लिए दी गई ड्यूटी में संलिप्त था जिससे डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए किए जाने वाले जन स्वास्थ्य उपाय प्रभावित हुए और (iii) कीट विज्ञान संबंधी प्रमुख संकेतकों, जिनसे वेक्टर घनत्व की प्रचुरता के बारे में पूर्व चेतावनी के संकेत मिलते हैं, की निगरानी में कमी देखी गई। वेक्टर घनत्व बढ़ने से यदि समयपूर्व निवारक कार्रवाई न की जाए तो संक्रमण के प्रसार में वृद्धि हो सकती है।

(ग): डेंगू वायरस से संक्रमित अधिकांश लोगों में लक्षण नहीं उभरे या साधारण बुखार जैसे हल्के लक्षण ही देखे गए, ऐसे मरीजों को केवल ओपीडी उपचार की आवश्यकता पड़ी। कुछ ही लोगों को गंभीर बीमारी और जटिलताओं के कारण अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता पड़ी। भारत सरकार को राज्यों से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि कोविड महामारी के कारण डेंगू रोगियों का उपचार प्रभावित हुआ हो। तथापि, ऐहतियाती उपाय के रूप में, वर्ष 2020 के दौरान भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान डेंगू मामला प्रबंधन पर विशेषज्ञों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय दिशानिर्देश तैयार किए थे, जिन्हें डीजीएचएस की अध्यक्षता में गठित संयुक्त निगरानी समूह (जेएमजी) द्वारा अनुमोदित किया गया था और जिन्हें कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और हितधारकों के साथ साझा किया गया था।

******